हमे उन महान चीजों का निर्माण करना चाहिए जो मौजूद नहीं है।
– अज्ञात

स्याह हुआ मर्दवाद का चेहरा

दूसरे स्कूल की प्रतियोगिता में पहुंचकर 'आधुनिक नारी की स्वातंत्र्य चेतना' जैसे किसी विषय पर जोरदार भाषण देकर आईं। स्कूल को फर्स्ट प्राइज मिला। सब गर्व से फूले–समाए, लेकिन असली सवाल किसी ने नहीं पूछा। जहां हमें सचमुच बोलना था, हम बोलीं क्यों नहीं?

मनीषा पांडेय।

इलाहाबाद की यह घटना करीब 23 साल पुरानी है। मेरी आर्यकन्या पाठशाला की दो शिक्षिकाएं लड़कियों को भेड़–बकरियों की तरह टैंपो में ठूंसकर दूसरी कन्या पाठशाला लेकर जा रही थीं, किसी वाद–विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। पास में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कैंपस था। टैंपो बैंक रोड पर मुड़ा तो साइकिल, मोटरसाइकिल से और पैदल चल रहे लड़कों के हुजूम में जाकर फंस गया। छात्रसंघ चुनाव सिर पर थे और सैकड़ों की तादाद में यूनिवर्सिटी के लड़के सड़क पर रैली निकाल रहे थे। तभी भीड़ में से एक लड़के ने कछुए की चाल से सरक रहे टैंपो के अंदर हाथ डाल खिड़की के पास बैठी लड़की के सीने पर हाथ मारा। लड़की की दबी हुई सी चीख निकली। 23 साल पहले छोटे शहर की डरपोक लड़कियां जोर से चीख भी नहीं पाती थीं। टीचर ने उलटे उसे ही डांट लगाई। बाकी लड़कियों को भी चुप रहने को कहा। टैंपो के अंदर एकदम सन्नाटा!

एक–दूसरे की हथेलियां कसकर पकड़े हुए लड़कियां शोर मचाते, चिल्लाते, पैंट की जिप पर हाथ मलते, आंख मारते, लार टपकाते हिंदुस्तानी मर्दानगी के उस जुलूस के गुजर जाने का इंतजार करती रहीं।

दूसरे स्कूल की प्रतियोगिता में पहुंचकर 'आधुनिक नारी की स्वातंत्र्य चेतना' जैसे किसी विषय पर जोरदार भाषण देकर आईं। स्कूल को फर्स्ट प्राइज मिला। सब गर्व से फूले–समाए, लेकिन असली सवाल किसी ने नहीं पूछा। जहां हमें सचमुच बोलना था, हम बोलीं क्यों नहीं? हमारी टीचर क्यों नहीं बोलीं? हमारे मां–बाप क्यों नहीं बोलते? कोई सही मौके पर सही बात बोलता क्यों नहीं?

कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया था 6 फरवरी को दिल्ली के गार्गी कॉलेज में, जब लड़कियों के एक सालाना जलसे में सैकड़ों की संख्या में लड़के घुस आए और अभद्रता की सारी हदें पार कर दीं। वे 'जय श्रीराम' के नारे लगा रहे थे, लड़कियों के सामने मास्टरबेट कर रहे थे, भीड़ में घुसकर लड़कियों को छू रहे थे। पूरी बेशर्मी और गुंडागर्दी के साथ घंटों ये सब होता रहा, लेकिन कैंपस के बाहर किसी को कानोंकान खबर नहीं हुई। मीडिया में भी घटना की रिपोर्ट हुई तीन दिन बाद। न कॉलेज प्रशासन जागा, न पुलिस आई। दिन–दहाड़े लड़कियों के कॉलेज में, उनके निजी और सुरक्षित स्पेस में घुसकर मर्दों ने सब जगह अपनी मर्दानगी के पोस्टर चिपका दिए और कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया।

कॉलेज की प्रिंसिपल ने जिस तरह पूरे मामले से पल्ला झाड़ा, मुझे अपनी आर्यकन्या पाठशाला की शिक्षिकाएं याद आ गईं। वह तो ऐसे बोल रही थीं कि लड़कियां ही जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने अपना दायरा तोड़ा, बाहर गईं। 23 बरस गुजर गए, लेकिन वह सवाल जस का तस है। जहां हमें सचमुच बोलना था, हम बोलीं क्यों नहीं? हमारी टीचर क्यों नहीं बोलीं? कॉलेज की प्रिंसिपल क्यों नहीं बोल रहीं, टीचर्स क्यों नहीं बोल रहे, मीडिया क्यों नहीं बोल रहा, संसद में बैठी औरतें क्यों नहीं बोल रहीं, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की बात करने वाले सत्तारूढ़ पार्टी के मर्द क्यों नहीं बोल रहे, सड़कों पर उतरकर लोग क्यों नहीं बोल रहे, पूरा देश क्यों नहीं बोल रहा?

वही पुरानी स्क्रिप्ट

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

बीते 23 सालों में इस मर्दवादी मुल्क की लड़कियों ने शिक्षा, नौकरी, रोजगार और आत्मसम्मान हासिल करने के लिए कितना लंबा सफर तय किया है, अपने लिए बोलना और लड़ना सीखा है, लेकिन हिंदुस्तानी मर्दानगी की स्क्रिप्ट इतने सालों में भी नहीं बदली है। वह उसी बेशर्मी और अहंकार के साथ बीच चौराहे पर खड़े मास्टरबेट कर रहे हैं और लड़कियां शर्म और डर से झुकी जा रही हैं। यह स्क्रिप्ट आखिर बदलेगी कैसे? नई कहानी कौन लिखेगा? जाहिर है वो नहीं, जिसे सारे बेशर्म, बेलगाम अधिकार हासिल हैं। नई कहानी वही लिखेंगी, जिन्हें पहले अपमानित किया गया और फिर कहा गया– चुप रहो।

संपादकीय

डॉगरलैंड का पुरातत्व

उत्तरी यूरोप में तेल और गैस की खोज पर्यावरण के लिए जितनी खतरनाक है, पुरातत्व के लिए यह उतनी ही फायदेमंद साबित हो रही है। ब्रिटेन के उत्तरी इलाकों के पूरब और हॉलैंड–डेनमार्क के पश्चिम में फैला विशाल समुद्र अभी यूरोप में खेती शुरू होने से ठीक पहले के इंसानों और मानवजाति के पहले से यूरोप में मौजूद लगभग इंसानी जीवों निएंडर्थल्स के बनाए औजारों की तलाश का सबसे बड़ा ठिकाना बन गया है। हालांकि इस समुद्र में मछुआरों के हाथ ऐसी चीजें लगने की शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी।

1931 में एक मछलीमार जहाज के जाल में तट से 40 मील दूर कोयले का एक अजीब लंबोतरा सा टुकड़ा फंस गया। इस टुकड़े को तोड़ने पर उसमें बारहसिंघे का एक 22 सेंटीमीटर (पौन फुट) लंबा सींग मिला, जिसे घिसकर भाले की तरह नुकीला बनाया गया था। कार्बन डेटिंग से सींग वाले जानवर का समय दो से आठ हजार ईसा पूर्व का निकाला गया। शिकारी इसका इस्तेमाल मछली मारने में करते रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया। फिर तो यहां विलुप्त मैमथ की सींग सहित खोपड़ी, निएंडर्थल इलाकों में पाया जाने वाला एक पत्थर का हथौड़ा और न जाने क्या–क्या मिलता गया। लेकिन ये सारी चीजें समुद्र में कैसे? भूगर्भशास्त्री इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आठ हजार साल पहले तक ब्रिटेन और उत्तरी यूरोप आपस में जुड़े थे और यह उथला समुद्र तब हर तरह के शिकार के लिए मुफीद एक छिछली–दलदली जगह हुआ करता था। समुद्री डूब के शिकार इस इलाके को कोई 25 साल पहले 'डॉगरलैंड' नाम दिया गया और फिलहाल यहां विंड फार्मिंग की हलचलें जारी हैं।

राजधानी के लोगों को लगता है कि केजरीवाल विकास के अपने अजेंडे को जारी रखेंगे और अपने वादों को पूरा करते हुए दिल्ली की चमक बढ़ाएंगे।

केजरीवाल की तीसरी पारी

नवीन वर्मा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल की तीसरी पारी शुरू हो चुकी है। इस बार उनसे अपेक्षाएं काफी बढ़ी हुई हैं, न सिर्फ दिल्ली के नागरिकों की बल्कि देश भर के लोगों की। राजधानी के लोगों को लगता है कि केजरीवाल विकास के अपने अजेंडे को जारी रखेंगे और अपने वादों को पूरा करते हुए दिल्ली की चमक बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ अन्य राज्यों के लोग यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वे विपक्षी राजनीति की धुरी बनकर उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। बहरहाल दिल्ली के लिए उन्होंने दस वादे किए हैं, जिन्हें दिल्ली वाले जल्द से जल्द पूरा होते देखना चाहेंगे। उनके वादों में कई ऐसे हैं, जिन पर काम पहले से ही चल रहा है, पर उन्हें एक मुकम्मल रूप दिया जाना जरूरी है, जैसे परिवहन की समस्या और महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले बंदोबस्त। लेकिन असल चुनौती प्रदूषण रोकने की है।

केजरीवाल ने वायु प्रदूषण के स्तर को घटाकर एक तिहाई तक लाने का लक्ष्य तय किया है और कहा है कि दो करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। उन्होंने यमुना की धारा को स्वच्छ और अविरल बनाने की बात भी कही है। यह पड़ोसी राज्यों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। देखना

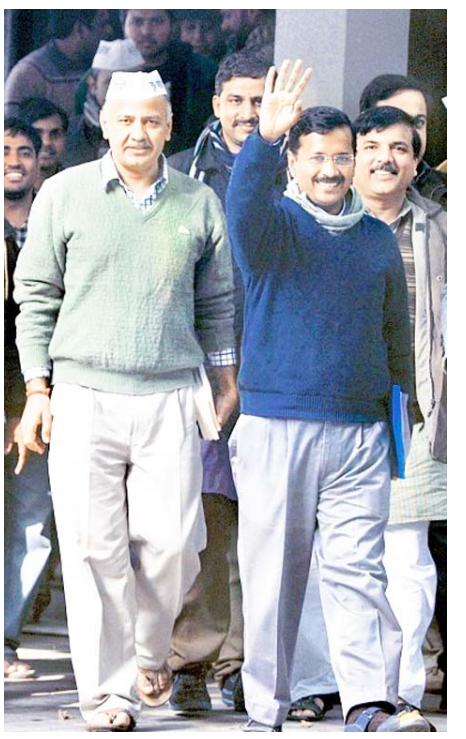

होगा कि केजरीवाल उन राज्यों के साथ मिलकर काम कर पाते हैं या नहीं। उन्हें केंद्र से इस बार भी ज्यादा सहयोग मिलने की उम्मीद नहीं है।

अगर दिल्ली को वाकई विश्वस्तरीय बनाना है तो यहां साफ–सफाई सुनिश्चित करना और झुग्गी–झोपड़ियों की बाढ़ को रोकना जरूरी है। ऐसे में केजरीवाल को हर झुग्गीवासी को अपना मकान देने का वादा पूरा करना ही होगा। वैसे उनके साथ एक सकारात्मक बात यह है कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। राज्य का वित्तीय घाटा राष्ट्रीय औसत से कम है और राजस्व संग्रह भी राष्ट्रीय औसत और पिछली राज्य सरकारों से बेहतर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली जबर्दस्त जीत के बाद कई विशेषज्ञ 'आप' को बीजेपी के विकल्प के रूप में देख रहे हैं और मान रहे हैं कि केजरीवाल तमाम अपोजिशन पार्टियों को एकजुट कर सकते हैं। अभी यह कहना मुश्किल है कि केजरीवाल अलग–अलग विचार रखने वाले वरिष्ठ विपक्षी नेताओं के साथ तालमेल बिठाकर चल पाएंगे या नहीं।

दूसरी बात यह है कि अभी तक उनकी राजनीतिक विचारधारा को लेकर भी संशय बना हुआ है। लेकिन समय का दबाव कई सबक सिखा देता है। 'आप' ने इसका संकेत भी दिया है। अब वह नीचे से अपना आधार बनाने पर जोर दे रही है। पार्टी ने देश के सभी स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। देखना है, केजरीवाल देश की राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं।

अष्टयोग-4959

1		3			6	
2	25		28	6	41	
	7	6				5
	38		24	4	29	
5		2		1		
	45	7	33		25	2
		5		3		1

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4958 का हल

2	1	7	5	3	6	4
7	39	6	33	4	33	5
4	7	5	1	2	3	6
3	36	4	28	1	29	7
6	4	3	5	7	2	1
5	29	1	33	6	32	2
1	7	2	4	5	6	3

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

ऑनलाइन फूड के बढ़ते कारोबार

मोहन। गूगल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन फूड ऑर्डर ऐप्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा युवा ज्यादा कर रहे हैं। वे हॉस्टलों, पीजी ठिकानों और दफ्तर में भी खाना मंगवाते हैं। ऑनलाइन फूड के बढ़ते कारोबार से रेस्टोरेंट और होटलों के कारोबारी परेशान हैं। होटल व्यवसाय से जुड़े कारोबारी ऑनलाइन फूड कंपनियों द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली भारी–भरकम छूट पर सवाल उठा रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलुरु, कोलकाता, गोवा, पुणे और वडोदरा के कई रेस्टोरेंट्स को इनसे काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी वजह से 15 अगस्त, 2019 से कई सारे रेस्टोरेंट्स ने ऑनलाइन फूड डिलिवरी कंपनियों से करार तोड़ दिया है। एनआरएआई यह भी चाहता है कि रेस्टोरेंट के पास ऑर्डर की डिलिवरी खुद करने या फूड डिलिवरी कंपनियों के डिलिवरी कर्मचारियों की सेवा लेने का विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। एनआरएआई के दबाव के कारण कुछ ऑनलाइन फूड कंपनियां अपनी मेंबरशिप स्कीमों में बदलाव लाने पर विचार कर रही है।